फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 | वर्षः 75 | संख्याः 287 | प्रभात | जयपुर, मंगलवार 20 मई, 2025 | डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत
Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

The Turning Point In Kargil War

The soldiers painstakingly crawled up the steep incline, inch by inch, a demanding vertical ascent, where every kilogram of weight felt tyrannical, two kilo food packets were relinquished in favour of more ammunition

World's Most Bizarre Museums

राहुल गाँधी ने जयराम रमेश को चुप कराया

'यह समय नहीं है, थरूर के खिलाफ बयानबाजी का, जब थरूर भारत के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत का पक्ष विदेश में समझाने-सुनाने के लिए'

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। राहुल गांधी ने शशि थरुर को लेकर कांग्रेस में चल रहे अंदरुनी संघर्ष पर फिलहाल विराम लगा दिया है। उन्होंने पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे थरुर के खिलाफ बयानबाज़ी बंद करें, खासकर तब, जब शशि थरुर अंतरराष्ट्रीय दौरों पर राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि इस समय पार्टी के आतंरिक मतभेद उजागर करना सही नहीं होगा, इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसा लगेगा कि कांग्रेस "तुच्छ राजनीति" कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को प्रतिनिधिमंडल के लौटने के बाद निपटाया जाएगा।

कांग्रेस के भीतर यह जबर्दस्त धारणा है कि जयराम रमेश ने मीडिया विभाग के प्रमुख पद का फायदा उठाते हुए अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर यह बयान दे दिया कि सरकार को कांग्रेस की ओर से भेजे गए चार नामों को राहुल गांधी

- राहुल ने जयराम से यह भी कहा, कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस अपनी अन्दरूनी लड़ाई में उलझी है, जबकि मसला देश की सुरक्षा व पाकिस्तान के आतंकवाद का है, अतः पार्टी के अन्दरूनी राजनीति के मामले बाद में निपटाये जा सकते हैं जब प्रतिनिधि मण्डल विदेश से लौट आये।
- कांग्रेस का एक धड़ा यह भी मान रहा है, कि पार्टी को इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, कि भारत सरकार किस-किस को प्रतिनिधि मण्डल में शामिल करना चाहती है।
- जयराम रमेश शायद यह कहकर, कि राहुल गाँधी ने चार नाम चुने हैं, जो प्रतिनिधि मण्डल में पार्टी की ओर से जायेंगे, बेवजह राहुल को इस विवाद में डाल दिया।
- अब, जयराम रमेश अपनी सफाई में यह कह रहे हैं कि संसदीय मामलों के मंत्री रिजिजू ने उनसे वो चार नाम मांगे, जिन्हें कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डल में शामिल कराना चाहती है, इसलिए उन्होंने चार नाम भेजे थे। पर, रिजिजू ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने कांग्रेस से चार नाम मांगे थे।
- दूसरी ओर शशि थरूर व मनीष तिवारी ने भी अपनी ओर से स्पष्ट किया कि वे प्रतिनिधि मण्डल में शामिल होंगे, अगर सरकार उन्हें आमंत्रित करती है।
- यह भी उल्लेखनीय है कि गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी शामिल किया गया है, सरकार की ओर से प्रतिनिधि मण्डल में, हालांकि, वे अब कांग्रेस में नहीं हैं।

ने मंजूरी दी है।

दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने उन चार नामों में से तीन को खारिज कर दिया और केवल आनंद शर्मा को स्वीकार किया। इसके अलावा, उन्होंने शशि थरुर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गैर सरकारी सदस्यों के बिना स्कूल फीस रिविज़न कमेटी की सुनवाई

जयपुर, 19 मई। स्कूल फीस से जुड़े विवादों की सुनवाई को लेकर रिवीज़न कमेटी नहीं बनने से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया है। मामले में अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी।

शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया है कि कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं और नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है। वहीं, आरटीआई अधिनियम में कमेटी के कोरम का भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में रिवीज़न

- शिक्षा सचिव ने हाईकोर्ट से कहा कि राज्य सरकार ने गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। अब गैर सरकारी सदस्यों के बिना 26 मई से सुनवाई शुरू होगी।

प्रार्थना पत्रों के लंबित प्रकरणों को देखते हुए इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार नहीं कर 26 मई से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी।

दरअसल भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। इस कमेटी के आदेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल विदेश भेजने के कार्यक्रम से अलग हुईं

सुदीप बन्दोपाध्याय व यूसुफ पठान को प्रतिनिधि मण्डल जाने से इन्कार करवाया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। केन्द्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस को, पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति पर भारत का पक्ष रखने के लिए विश्व के प्रमुख देशों की यात्रा करने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन पार्टी के संसदीय दल के दो सदस्यों ने अंतिम समय पर प्रतिनिधिमंडल से नाम वापस ले लिया। प्रारंभ में केन्द्र ने सुदीप बंद्योपाध्याय को प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन अंतिम सूची तैयार होने से पहले ही सुदीप ने भारत का पक्ष रखने जैसे कार्यों से खुद को अलग कर लिया।

दूसरा नाम यूसुफ पठान का सामने आया, जो चयन प्रक्रिया की रणनीतिक सोच को दर्शाता था। सत्तारूढ़ पार्टी ने उन्हें आमंत्रित किया, क्योंकि वे निस्संदेह भारत का प्रतिनिधित्व प्रभावी रूप से करते। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया और पठान को प्रतिनिधिमंडल से हटने के लिए मजबूर किया।

यह एक अपमानजनक स्थिति थी,

- सरकार, जबकि, इन दोनों को जरूर शामिल करना चाहती थी, ऑपरेशन सिन्दूर में भारत का पक्ष विदेश में प्रस्तुत करने के लिए, विदेश भेजने के लिए।
- ममता बनर्जी ने यह तर्क दिया कि सरकार ने इन दोनों सांसदों से सीधे बात कैसे की, प्रतिनिधि मण्डल में शामिल करने के बारे में, क्योंकि यह अधिकार तो पार्टी का है, कि किसको बाहर भेजना चाहिए। सांसदों से सीधे बात करके, सरकार ने पार्टियों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने की चेष्टा की है।
- पर, ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को प्रसन्न रखने के लिए मुस्लिम मतदाताओं के पक्ष में सबसे ज्यादा आक्रामक नज़र आना चाहती हैं, अतः सांसदों को प्रतिनिधि मण्डल में शामिल होने से रोका था। अगले वर्ष बंगाल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिन्दूर को समझाने के लिए अपने सांसदों को, विदेश जाने से रोका, अब ममता बनर्जी के लिए, मुस्लिम मतदाताओं का सबसे बड़ा हितैषी होने की छवि बनाना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि कई मुस्लिम पार्टियों ने अगले चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का निर्णय ले लिया है।

क्योंकि यह प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला था। पठान को इसलिए भी हटाया गया क्योंकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आगामी अगस्त से भारत में "गैलप पोल्स" शुरू होंगे

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 19 मई। भारत में पहली बार एक रियल-टाइम पोलिटिकल परसैप्शन इंडैक्स (पी पी आई) लाने की तैयारी है। "पोल फर्स्ट" नामक यह नई वैब मैग्ज़ीन 3 अगस्त से लॉन्च होगी, जिसे भारत का "गैलप" कहा जा रहा है। गैलप एक विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी शोध, विश्लेषण और परामर्श संस्था है, जो मुख्य रूप से जनमत सर्वेक्षण के लिए जानी जाती है। पोलिटिकल अप्रूवल रेटिंग्स को संस्थागत रूप देने की दिशा में यह एक साहसिक कदम है।

पी पी आई हर सप्ताह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में जनमत, और क्षेत्रीय स्तर पर मददाता झुकाव को वैज्ञानिक डेटा के आधार पर ट्रैक करेगा और प्रकाशित करेगा। यह प्रयास 25 वर्षों के राजनैतिक डेटा विश्लेषण के अनुभव पर आधारित है।

इसकी साप्ताहिक रिपोर्टें सार्वजनिक होंगी, तथापि, चुनिंदा पत्रकारों और संपादकों के लिए एक सीमित सब्सक्रिप्शन ऑफर 1 लाख रु. प्रतिमाह की कीमत पर उपलब्ध बताया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं - कच्चे डेटा तक पूर्ण पहुंच (सी एस वी फॉर्मेट में, सैम्पल बेट्स सहित), सत्यापन उपकरण (उत्तरदाताओं की संख्या और टाइम स्टैम्प्स), सार्वजनिक रिलीज से पहले रिपोर्ट छापने के लिए 3 घंटे का समय तथा विश्लेषण की पूरी पारदर्शिता।

अपने परिचय में "पोल फर्स्ट" कहता है कि यह भारत में एक पारदर्शी, सत्यापन करने योग्य और राजनीतिक भावना नापने की सुसंगत प्रणाली है, जो हमारे लोकतंत्र में लंबे समय से अनुपस्थित रही है।

पोल फर्स्ट के पोलिटिकल मार्केटिंग कंसल्टैंट श्रेणिक जैन द्वारा भेजे गये ईमेल में कहा गया है कि अगर यह पहल आपके न्यूजरूम की समयबद्ध और तथ्य आधारित राजनैतिक रिपोर्टिंग की प्रतिबद्धता से मेल खाती है, तो पोल फर्स्ट आपको 3 अगस्त, 2025 को सुबह 11 बजे से पहले ही अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करना चाहेगा।

यह हर सप्ताह भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक भावना को ट्रैक करेगा, भारत के राजनीतिक मूड पर नजर रखेगा, दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा और उनका विश्लेषण करेगा कि वे क्यों प्रासंगिक हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की ओवर ऑल अप्रूवल रेटिंग देगा और पूछेगा- क्या आप प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं? और यदि आज चुनाव होते, तो आप किस पार्टी या गठबंधन को वोट देते?

यह रिपोर्ट 2024 के वोट जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का अंतर

- यह पोल, जो लगातार साल भर ही चलता रहेगा, भारत का राजनीतिक वातावरण व राजनीतिक दलों व नेताओं की जनता में लोकप्रियता लगातार आंकेगा तथा अपना आकलन जनता के सामने लगातार रखेगा।
- इस से, हर मुद्दे पर जनता क्या सोच रही है, ज्ञात होगा, तथा राज्य व केन्द्रीय सरकार को अपना रवैया व सोच बदलने का मौका मिलता रहेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कॉलेज शिक्षकों का रिटायरमैंट भी 65 साल में क्यों नहीं हो-हाईकोर्ट

जयपुर, 19 मई। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूछा है कि मैडिकल शिक्षकों की तरह कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमैंट उम्र 65 साल क्यों न कर दी जाए। हाई कोर्ट ने इस बारे में प्रमुख विधि सचिव, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और यूजीसी सहित अन्य को

- केन्द्र सरकार, यूजीसी, मेडिकल शिक्षक तथा डेढ़ दर्जन राज्यों में शिक्षकों की रिटायरमैंट आयु 65 वर्ष की जा चुकी है।

नोटिस भेजकर जवाब माँगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश डॉ. विश्राम लाल बैरवा और अशोक कुमार अग्रवाल सहित, अन्य की याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुप्रिय और अक्षय दत्त शर्मा ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार और यूजीसी कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमैंट उम्र 65 साल करने का प्रावधान कर चुके हैं। प्रदेश में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिलायंस ने एशिया का वर्ष 2025 का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय ऋण प्राप्त किया

इस ऋण का पहला भाग 2.43 बिलियन डॉलर का है, तथा दूसरा भाग 67.7 बिलियन जापानी मुद्रा येन का है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने 2.9 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डुएल करैंसी सिंडिकेटेड लोन डील हासिल की है, यह 2025 में एशिया की सबसे बड़ी डील है और पिछले दो वर्षों में किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा लिया गया यह सबसे बड़ा कर्ज़ है। यह वित्तीय सौदा दो भागों में विभाजित है: एक भाग में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और दूसरे भाग में 67.7 बिलियन (लगभग 462 मिलियन डॉलर) जापानी येन। विश्व की कुल 55 देशों के बैंकों ने इसमें भाग लिया, जिससे यह वर्ष का एशिया का सबसे बड़ा ऋण देने वाला संघ बन गया।

यह डील केवल एक वित्तीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह आरआईएल की वित्तीय ताकत और वैश्विक बाज़ारों में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा पर एक ठोस विश्वास की मुहर है। बढ़ती ब्याज दरों, भू-राजनीतिक तनाव और सीमित पूंजी के दौर में इतना बड़ा लोन हासिल करना रिलांयस की बेहतरीन क्रेडिट प्रोफाइल और वैश्विक आकर्षण को दर्शाता है।

इस विश्वास के मूल में रिलांयस का विविधतापूर्ण मॉडल है, जो ऊर्जा, पेट्रोकैमिकल्स, टैलिकॉम (जियो), रिटेल, डिजिटल सेवाएं और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में रिलायंस अग्रणी है, जिससे एक संतुलित पोर्टफोलियो बनता है, जो किसी एक क्षेत्र में आए उतार-चढ़ाव से कंपनी को बचाता है। यही विविधता निवेशकों को दीर्घकालिक आय और स्थिरता के प्रति आश्वस्त करती है।

इस विश्वास को और मजबूती मिलती है रिलांयस की इन्वेस्टमैंट-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग्स से, जो भारत की संप्रभु रेटिंग से भी ऊपर हैं। मूडीज ने आरआईएल को बीएए2 और फिंच ने बीबीबी रेटिंग दी है, दोनों ही भारत से एक स्तर ऊपर हैं। उभरते बाज़ारों की कंपनियों में यह दुर्लभ उपलब्धि है, जो कंपनी की सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मजबूत पूंजी प्रवाह और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है।

यह हाई रेटिंग रिलायंस को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी देती है। इससे पूंजी तक आसान पहुंच मिलती है, जो ग्रीन एनर्जी और 5जी जैसी परियोजनाओं के लिए बेहद अहम है। वित्तीय संस्थान उन कंपनियों को ऋण देना पसंद करते हैं, जिनका दृष्टिकोण स्थिर हो और भुगतान का इतिहास मजबूत हो, रिलांयस की ऐसी ही छवि है।

इस ऋण की डुएल करैंसी संरचना आरआईएल की परिपक्व वित्तीय रणनीति को दर्शाती है। विभिन्न मुद्राओं में ऋण को विभाजित करना मुद्रा विनिमय दरों की अस्थिरता से बचाव, उधारी लागत में कमी और विविध नकदी स्त्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से, येन मुद्रा का होना यह दर्शाता है कि जापानी निवेशक भारतीय कॉर्पोरेट्स को ऋण देने में रुचि दिखा रहे हैं और रिलांयस बहु-विनियोग आधारों से पूंजी

- यह ऋण देने के लिए 55 अन्तरराष्ट्रीय स्तर के बैंक मिले और इस ऋण के लिए फायनैंस का इन्तजाम किया।
- यह ऋण एशिया का इस वर्ष का सबसे बड़ा ऋण है।
- हालांकि, इस वर्ष एशिया की लगभग सभी बड़ी कम्पनियां और बैंक ऋण लेने व देने में काफी कतरा रहे हैं, अतः यह विशेष रूप से सराहनीय है, कि फायनैंशियल दृष्टि से इस मायूस से वातावरण में भी रिलायंस ने इतना बड़ा ऋण लेकर, मायूसी के वातावरण में छेद कर दिया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विदेश मंत्री के वक्तव्य ने प्र.मंत्री मोदी को अटपटी स्थिति में डाला

विदेश मंत्री ने मीडिया के समक्ष कहा कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन (ऑपरेशन सिन्दूर) के बारे में पहले ही बता दिया था

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 19 मई। सुरक्षा संबंधी एक बहुत बड़ी गलती, जिसमें विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर लिप्त हैं, के रहस्योद्घाटन के बाद एक बड़ा राजनैतिक तूफान खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि जयशंकर ने पाकिस्तान को उसके आतंकी ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक से जुड़ी अतिसंवेदनशील कार्यवाही की जानकारी दे दी थी। इस रहस्योद्घाटन के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ तो इसकी कड़ी आलोचना कर ही रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी दबाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री, विदेश नीति की इस नाकामी पर आक्रोश और आलोचनाओं से घिर गये हैं।

वरिष्ठ राजनयिकों और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, डॉ. जयशंकर के मीडिया को दिये गये इस बयान, कि भारत की आतंकी-विरोधी कार्यवाही की अग्रिम सूचना पाकिस्तान को दे दी गई थी, ने इस सामरिक लीकेज के बारे में गंभीर चिन्ताएं खड़ी कर दी हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है कि इस अभूतपूर्व कदम से, असावधानीवश, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे प्रमुख आतंकी आकाओं को इस सटीक हमले से बचने का समय मिल गया हो और ऑपरेशन सिंदूर नामक इस मिशन के असली उद्देश्य को क्षति पहुंची हो।

एक शीर्ष विदेश नीति विश्लेषक ने कहा, "यह मात्र एक राजनयिक गलत कदम नहीं है, यह निर्णय लेने में की गई एक बेहद गंभीर गलती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।"

उन्होंने आगे कहा, "एक सुनियोजित सैन्य कार्यवाही की जानकारी आतंकियों को पनाह और संरक्षण देने वाले देश को दे देने से सैन्य कार्यवाही का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है तथा इस कदम के पीछे के रणनैतिक इरादे के बारे में प्रश्न खड़े होते हैं।

पूर्व विदेश मंत्री यशवन्त सिन्हा ने राजनैतिक मोर्चा संभालते हुए, सर्वोच्च स्तर पर जवाबदेही की मांग की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खामोशी पर प्रश्न खड़े किये हैं तथा कहा है कि जनता सुस्पष्ट स्पष्टीकरण की हकदार है। सिन्हा ने कहा, "यह केवल जयशंकर की चूक नहीं है, यह राष्ट्र-हित की रक्षा करने के मामले में नेतृत्व की असफलता है।"

भाजपा तथा उसकी वैचारिक मार्गदर्शक संस्था आर एस एस के अंदरूनी सूत्र भी बढ़ते जा रहे आंतरिक असंतोष की पुष्टि कर रहे हैं। भगवा खेमे के अनेक लोगों का मानना है कि मोदी की मजबूत नेता की छवि पर इस विदेश नीति-कुप्रबन्धन की काली छाया पड़ी है। यह आलोचना इसलिए और प्रबल हुई है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने एयर स्ट्राइक के बाद, अप्रत्याशित रूप से युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने का दावा किया, और प्रधानमंत्री ने उनके दावे को नियंत्रित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नामोल्लेख न करने की शर्त पर बताया, "ट्रम्प के हस्तक्षेप तथा उनके प्रचार से भारत की छवि, उसकी अपनी क्षेत्रीय लड़ाई में गौण हो गई। - - यह एक कूटनीतिक लज्जा की बात थी तथा प्रधानमंत्री को इसे पूरी सख्ती से रोकना चाहिए।"

विपक्षी नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए, मोदी की विदेश नीति को प्रतिक्रियाशील एवं असंगत बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस प्रकरण को "कूटनीति एवं नेतृत्व की असफलता" बताया है तथा भारत के पिछले वर्ष की राष्ट्रीय सुरक्षा की कार्यवाहियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चूंकि दबाव बनता जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह जरूरी है कि वे इस पूरे मामले को नियंत्रण में लेने के लिए, इस मुद्दे को सीधे ही अपने हाथ में लें। राष्ट्रीय सुरक्षा, जो मोदी के राजनीतिक प्रभाव की धुरी रही है, के बारे कमजोरी की धारणा उन्हें चुनाव में महंगी पड़ सकती है।

इस विवाद के परिणामस्वरूप, ऑपरेशन सिंदूर के संचालन तथा उसमें विदेश मंत्रालय की भूमिका की संसदीय जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। लोगों का मानना है कि इस समय प्रधानमंत्री की खामोशी उन सवालों को और बड़ा रूप दे रही है, जो एक नाज़ुक मोड़ पर लड़खड़ाती हुई विदेश नीति से जुड़े हैं।

- विदेश मंत्री के इस वक्तव्य से कई सवाल उठते हैं। क्या इस सूचना ने आतंकवादियों के संगठनों को अपने आतंकवादी शिविर छोड़ कर अन्यत्र चले जाने का मौका दे दिया। और इसीलिए हाफिज़ सईद व मसूद अज़हर बच निकले।
- पूर्व विदेश मंत्री यशवन्त सिन्हा सबसे ज्यादा सक्रिय रहे, प्र.मंत्री को इस मुद्दे पर कठघरे में खड़ा करने में।
- यहां तक कहा जा रहा है, कि विदेश मंत्रालय की इस त्रुटि ने मोदी सरकार की विदेश नीति की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है, और ऑपरेशन सिन्दूर की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, तो विदेश नीति का "फेलियर", भारत के पक्ष में कोई भी देश, सिवाय रूस के, खड़ा नजर नहीं आया।
- साथ ही ट्रम्प के इस दावे ने, कि उसने मध्यस्थता करके व व्यापारिक हितों का तकाजा करके दोनों देशों के बीच 'सीज़ फायर' करवाया, भारत की व मोदी की मजबूत छवि पर, ग्रहण सा लगा दिया था, और विदेश मंत्रालय इस छवि को अभी तक पूर्णतया साफ नहीं कर पाया है।